PUNE RESEARCH SCHOLAR ISSN 2455-314X
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL VOL 5, ISSUE 2

भारतीय वस्त्र उद्योग का विकास, अर्थव्यवस्था व् रोजगार में इसका योगदान, वस्त्र नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी स्थिति का विवेचनात्मक अध्ययन

डॉ. रोहित अग्रवाल
असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य विभाग
एम. जी. एम. डिग्री कॉलेज,
संभल (उ.प्र.) भारत

वैसे तो वस्त्र उद्योग एक शताब्दी पुराने टैक्सटाइल इंडस्ट्री का ही एक हिस्सा है लेकिन यह एक अलग उद्योग के रूप में अपनी पहचान देश विभाजन के बाद ही बना पाया। हर दिन आदमी की पॉकेट और मन में खास जगह बनाने वाले इस उद्योग की सफलता के पीछे सरकार की उदारवादी नीतियाँ भी है। 1975 में सरकार ने उन्हीं नीतियों के तहत अनौपचारिक और लघु इकाई वाले गारमेंट सैक्टर को प्रोत्साहित करने का फैसला लिया। इस सरकारी फैसले से वस्त्र उद्योग ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी अलग व महत्वपूर्ण छाप छोड़ी,रोजगार के अनेक अवसर सृजित किये जिसमे लाखो स्त्री-पुरुष काम करते आ रहे हैं व् इसने देश की अर्थव्यवस्था को भी काफी सशक्त किया |भारतीय वस्त्र उद्योग का देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान है। जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता होने के साथ ही इसका देश के इंडस्ट्रियल उत्पादन, रोजगार के सृजन और निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी इसका केंद्रीय योगदान है। देश के इंडस्ट्रियल उत्पादन में 14 प्रतिशत, सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत तथा निर्यात आय में 13.50 प्रतिशत वस्त्र उद्योग का योगदान है। वस्त्र उद्योग देश के 35 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। महिलाओं और पुरूषों की एक बड़ी संख्या इस क्षेत्र से अपनी आजीविका अर्जित कर रही

है। वस्त्र उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। इस प्रकार, इस उद्योग का सर्वांगीण विकास देश की अर्थव्यवस्था के सुधार को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। पिछले कुछ समय से सरकार ने नीतिगत उपाय शुरू कर वस्त्र उद्योग को पिछले पांच दशक के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है | इस शोधपत्र में मैंने भारतीय वस्त्र उद्योग का विकास, अर्थव्यवस्था व् रोजगार में इसका योगदान,वस्त्र नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसकी स्थिति का गहन विवेचनात्मक अध्ययन स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का पूर्ण व् सार्थक प्रयास किया है |

मुख्य शब्द – भारतीय वस्त्र उद्योग, वस्त्र नीति, रोजगार, अवसर, अर्थव्यवस्था, योगदान, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार, निवेश, उत्पादन, विकास

प्रस्तावना -

भारत में वस्त्र का मुख्य काम दिल्ली, मुबई, बंगलुर, त्रिपुर (हौजरी) मद्रास और कोलकत्ता में होता है यहाँ से तैयार होने वाला माल ज्यादातर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को जाता है। जापान, स्विट्ज़रलैंड, रूस, स्वीडन और आस्ट्रेलिया भी भारतीय गारमेंट का आयात करते हैं। इस लाभदायक उद्योग ने भारत में लाखों को रोजगार के अवसर प्रदान किये हैं। लेकिन लोगों के जिस्मानी सौदर्य में गारमेंट के जरिये इजाफा करने वाले मजदूर तबके का आर्थिक शोषण बदस्तूर जारी है। इसमें अधिकतर औरतें व लड़कियाँ काम करती हैं। गारमेंट उद्योग से जुड़े मजदूर असंगठित हैं और वे मालिक के साथ मोलभाव भी नहीं कर सकते। ज्यादा मोलभाव का अर्थ काम से छटनी होना है। निर्यात अभिमुखी गारमेंट इंडस्ट्री में ज्यादातर प्रवासी मजदूर तबका ही अपना पसीना बेचता है। तब तबके की महिलाएं और बच्चे भी सस्ती दरों पर इस काम को करने को तैयार हो जाते हैं।

महिलाएं औसतन रोजाना 8-9 घंटे और बाल मजदूर 10-12 घंटे काम करते हैं। बंगलुर के वस्त्र उद्योग में अंदाज 25,000 कामगार है जिनमें 80 प्रतिशत महिलाएं हैं। ये महिला मजदूर बहुत ही सस्ती मजदूरी पर काम करती हैं। कारण कुछ न मिलने से कुछ ही मिल जाय वाली स्थिति की मानसिकता है। काम में देरी या दूसरे कारणों से इन्हें अपमानित

भी किया जाता है।तमिलनाडु, के त्रिपुर क्षेत्र के वस्त्र उद्योग में अंदाजन 300,000 कामगार काम करते हैं उनमें 14 साल से कम उम्र के बाल मजदूरों की संख्या अनुमानतः 10,000 से 90,000 के बीच आंकी जाती है। 'सेंटर फॉर सोशल एजुकेशन एंड डेवलोपमेंट' नामक और गैर सरकारी संगठन ने 1995 में चाइल्ड लेबर एन हौजरी इंडस्ट्री आफ त्रिपुर शीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की। अध्ययन रिपोर्ट में वस्त्र उद्योग में मजदूरों की इतनी बड़ी तादात में जुड़ने के पीछे काम करने वाले कारणों को जानने की कोशिश की गई है। अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार पुल और पुश फैक्टर काम कर रहे हैं। खींचने वाले कारणों का सीधा सम्बन्ध उद्योग से है और धकेलने वाले कारकों में परिवार, माँ-बाप की सामाजिक-आर्थिक मुख्यतः जिम्मेदार है। खिंचाव कारकों में उद्योग का विस्तार और ढांचा आता हैं माल की मांग के साथ-साथ बाल मजदूरों की भी संख्या बढ़ने लगी। इस इंडस्ट्री में बाल मजदूर जिस तरह का काम करते हैं। उसके लिए उन्हें खास प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती। एक-दो महीने का प्रशिक्षण ही काफी होता है। उनका मुख्य काम होता है: दर्जी की मदद करना, कपड़ा, इकट्ठा करना कपड़ा मोड़ना, कपड़े से फालतू धागे काटना आदि। मजदूर कपड़ों को रंगने और ब्लीचिंग इकाइयों में भी काम करते हैं।आकर्षित करने वाले कारणों में एक मुख्य कारण वस्त्र उद्योग को मजदूरों की दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तुलना में ज्यादा दिहाड़ी मिलना भी है।

हालाकि मजदूरों का स्वास्थ्य भी बुरी तरह से प्रभावित होता है। इन निर्माण इकाइयों में हवा निकासी का उचित प्रबंध नहीं है। साँस घुटता है। बुनाई वाले कमरों में सांस लेने में तो केमिकल धूल के कारण हवा ज्यादा ही प्रदूषित रहती है। यहाँ काम करने वालों को अक्सर बुखार, टाइफइड' रहता है। काटन डस्ट फेफड़ों पर बुरा असर छोड़ती है और इससे टी.बी होने की आशंका बनी रहती है। आँख में भी कई रोग लग जाते हैं। त्वचा रोग भी पैदा होती हैं। त्रिपुर का पानी भी स्वस्थ के लिए हानिकारक है। इसलिए बच्चे जल्दी ही बीमारियों से घिर जाते हैं। स्लम इलाकों में पानी के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिलता और पानी की निकासी का भी प्रबंध नहीं होता। नतीजन ये बात मजदूर प्रदूषित पानी पीने, प्रदूषित हवा में साँस लेते हैं। हालाँकि भारतीय वस्त्र उद्योग में अधिकतर महिलाएं और बालिका मजदूर ही काम करती हैं लेकिन इनकी सही संख्या बावत आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

भारतीय वस्त्र उद्योग का निरंतर अंतर्राष्ट्रीयकरण होने से घरेलू उत्पादन में महिला कामगारों की संख्या में बढोत्तरी हुई है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से दो प्रकार की योजनाएं बनाती हैं, एक उन क्षेत्रों तथा देशों में स्थापित उद्योग किया जाता है जहाँ श्रमिक कम मजदूरी पर मिल जाते हैं, दूसरा हर देश की श्रम शक्ति के असुरक्षित वर्ग का उपयोग करना जैसे प्रवासी तहत महिलाएं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारत में वस्त्र उद्योग, फैक्ट्रियों के रूप में प्रस्थापित नहीं किया जाता। वास्तव में स्थानीय कपड़ा निर्माता अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों तथा निर्माता कम्पनियों से सम्पर्क बना कर रखती हैं।

विश्व पुनसंरचना की इस प्रक्रिया में सबसे अधिक और महत्वपूर्ण सम्पर्क घरेलू महिला कामगारों से होता है परम्परागत मान्यताओं एवं रोजगार के अवसरों के अभाव के कारण गृहिणियां एवं लड़कियाँ कपड़ा उत्पादन से जुडती है| कपड़ा का उद्योग सम्पर्क विदेशी बाजार से होता है। अतः वे अपना काम सब कांट्रेक्टिंग और छोटे कार्यस्थलों पर करवाते हैं। परिणामस्वरुप संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों के बीच अंतर प्रायः अस्पष्ट हो जाता है फैक्ट्री का सम्पर्क गृहणियों के घरों से लेकर विश्व बाजार तक होता है। भारत से कपड़े के कुल वार्षिक निर्यात में दिल्ली का 60 प्रतिशत योगदान होता है। इस उद्योग से लगभग एक लाख कामगार जुड़ें हैं जिनमें से 75 प्रतिशत पुरुष व् 25 प्रतिशत महिलाएं हैं।

भारतीय वस्त्र उद्योग का देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान है। जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता होने के साथ ही इसका देश के इंडस्ट्रियल उत्पादन, रोजगार के सृजन और निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी इसका केंद्रीय योगदान है। देश के इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन में 14 प्रतिशत, सकल घरेलू उत्पाद में 4 प्रतिशत तथा निर्यात आय में 13.50 प्रतिशत वस्त्र उद्योग का योगदान है। वस्त्र उद्योग देश के 35 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। महिलाओं और पुरूषों की एक बड़ी संख्या इस क्षेत्र से अपनी आजीविका अर्जित कर रही है। वस्त्र उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। इस प्रकार, इस उद्योग का सर्वांगीण विकास देश की अर्थव्यवस्था के सुधार को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।

पिछले कुछ समय से सरकार के माध्यम से नीतिगत उपाय शुरू किए जाने के वजह से, वस्त्र उद्योग पिछले छः दशक के मुकाबले आज कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। मूल्य के हिसाब से यह उद्योग जहां पांच दशक पहले 3 से 4 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा था वहीं आज 8 से 9 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ रहा है। प्रगतिशील घरेलू अर्थव्यवस्था, कपास उत्पादन में बढोत्तरी, अनुकूल वस्त्र नीति तथा २१वी सदी के शुरूआती वर्ष में समाप्त की गई बहुरेशा व्यवस्था के कारण इस क्षेत्र के विकास में काफी तेजी आई । पिछले कुछ सालों से लागू उचित कराधान नीति के कारण सभी विभागों में अवसरों की एकसमान उपलब्धता ने भी इस क्षेत्र के उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस क्षेत्र की इंडस्ट्रीज के लिए एक मजबूत नींव रखी जा चुकी है, जिस पर विश्वस्तरीय उत्पादन इकाइयां अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग कर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर में एक स्थान बना सकते हैं। पिछले कुछ समय से सरकार के नीतिगत उपाय की शुरुआत की वजह से, वस्त्र पिछले उद्योग छः दशक के मुकाबले आज कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। मूल्य के हिसाब से यह उद्योग जहां छः दशक पहले 3 से 4 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा था वहीं आज 8 से 9 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ रहा है। वस्त्र उत्पादन और निवेश में लगातार बढ़ोतरी से इस उद्योग का विकास प्रदर्शित होता है।

वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, देश के व्यापारिक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 13.5 प्रतिशत की है। मल्टी फाइबर व्यवस्था (एमएफए) के समाप्त होने के बाद नई तकनीकों और क्षमता विकास के द्वारा उद्योग ने विकास की नए सोपान तय किए हैं। एमएफए के बंद होने के एक साल के भीतर भारतीय निर्यात में 22 प्रतिशत की दर से विकास हुआ है।

वस्त्र उद्योग एक निर्यात प्रधान उप-क्षेत्र है जो कुल भारतीय वस्त्र निर्यात में 40-45% का योगदान देता है। यह एक कम निवेश आवश्यकता और श्रम प्रधान है: उपक्षेत्र में 1.00 लाख रुपए का निवेश 6-8 नौकरियां सृजित करता है।

लघु उद्योग के लिए रखे गये परिधान उत्पाद आरक्षित कर दिए जाने के कारण कपड़ा उद्योग की वृद्धि अवरुद्ध हो गई थी । परिणामस्वरूप, परिधान इकाईयां ना तो अर्थव्यवस्था की

अधिकतम पैमाने को प्राप्त कर पाईं और न ही अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाले वस्त्रों का उत्पादन कर सकीं। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बने बनाए वस्त्रों का निर्यात 13 .72 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा । इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव तब देखा गया,२१वी सदी के पहले दशक तक इस उप क्षेत्र में 21.800.00 करोड़ रुपये की निवेश की आवश्यकता होगी, जो 56.40 लाख लोगों के लिये रोजगार पैदा करेगा, जिसमें से 28.25 लाख लोग अर्ध प्रशिक्षित और 11.30 लाख लोग अप्रशिक्षित होंगे। वस्त्र और परिधान के उप क्षेत्र में रोजगार और निर्यात की क्षमताओं को देखते हुए, सरकार इसके विकास और विस्तार को प्राथमिकता देगी। कठोर श्रम कानूनों में सुधार के प्रयास किये जायेंगे और सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिये ब्रांड को बढ़ावा दिया जाएगा। कामन डेटा प्रदान करने के लिए और वस्त्र उद्योग के लिये बिक्री के प्रतिष्ठानों की स्थापना की जायेगी।

सरकार योजना के तहत, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ली जाने वाले ब्याज राशि के 5% (कताई क्षेत्र के लिए 4%) की वापसी सुनिश्चित करती है, जिससे प्रौद्योगिकी उन्नयन की योजना बना रही इकाइयों के पास क्रेडिट की उपलब्धता बनी रहे। वस्त्र और जूट सब-सेक्टर से जुड़ी लघु इकाइयों के लिए ब्याज दर में मिलने वाली पांच प्रतिशत की सब्सिडी के स्थान पर मार्जिन राशि में 15 प्रतिशत की राहत दी जाती है। वहीं विकेंद्रीकृत हथकरघा इकाइयों को टीयूएफएस योग्य मशीनरी में निवेश के लिए 20 प्रतिशत मार्जिन मनी राहत ब्याज में मिलने वाली 5 प्रतिशत की छूट के बदले उपलब्ध कराई जाती है। वस्त्रों के प्रसंस्करण के लिए तकनीकी रूप से आवश्यक मशीनों के लिए योजना के तहत पूंजी लागत में दस प्रतिशत की राहत ब्याज राहत के पांच प्रतिशत के अलावा प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत आयात की जाने वाली पुरानी मशीनें सहायता या छूट के लिए पात्र नहीं हैं। ऐसे पुराने शटलरहित करघे जिनका मूल्य आठ लाख रुपए से ज्यादा न हो और जो कम से कम दस साल तक काम लायक हों इसका अपवाद हैं। इस योजना का लाभ वस्त्र उद्योग के लगभग सभी क्षेत्रों को मिलता है। वस्त्र उद्योग ने पिछले पांच वर्षों के दौरान निवेश में उछाल देखा है । संचयी निवेश रुपए 1,51,338 करोड़ रुपए का रहा है। निवेश का मुख्य कारण प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टीयूएफएस) रहा है। निवेश में होने वाली बढोत्तरी

प्रौद्योगिकी उन्नयन, विकास की संभावना वाले क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास को मजबूत करने के अलावा अतिरिक्त स्पिंडल्स और करघों की स्थापना को बढ़ावा देगी।

इसके अलावा यह योजना वस्त्र निर्माण, तकनीकी वस्त्रों और वस्त्रों के प्रसंस्करण जैसे विकास की भारी संभावना वाले क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन और रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान तकनीकी वस्त्र विकास एवं उन्नयन योजना सरकार के माध्यम लागू की जाएगी। स्कीम के तहत 44 करोड़ की लागत से चार उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इनमें से एग्रोटेक, बिल्डटेक, मेडीटेक और जियोटेक के लिए एक-एक उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की जाएगी। संश्लेषित और कला रेशम मिल अनुसंधान संगठन, मुंबई मानवनिर्मित वस्त्र अनुसंधान संस्थान, सूरत और नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी, नवसारी, गुजरात को एग्रोटक तकनीकी वस्त्र विकास के लिए नामित किया गया है। उत्तर भारतीय वस्त्र अनुसंधान संगठन, गाजियाबाद को भारतीय तकनीकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के साथ प्रोटेक तकनीकी वस्त्र विकास के लिए नामजद किया गया है। अहमदाबाद वस्त्र उद्योग संगठन, अहमदाबाद और बॉम्बे वस्त्र अनुसंधान संगठन, मुंबई को जियोटेक तकनीकी वस्त्र विकास हेतु चुना गया है। दक्षिण भारत वस्त्र अनुसंधान संगठन, कोयंबटूर और एसी महाविद्यालय, कोयंबटूर को मेडीटेक तकनीकी वस्त्र विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जियोटेक वस्त्र उत्कृष्ट केंद्र का बॉम्बे वस्त्र अनुसंधान संगठन, मुंबई में उद्घाटन किया जा चुका है जबकि जियोटेक उत्कृष्ट केंद्र जल्द ही कोयंबटूर में काम करना प्रारंभ कर देगा।

सरकार ने तकनीकी वस्त्र उद्योग मिशन को पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित करना प्रस्तावित किया है। मिशन के तहत वस्त्र उद्योग के लिए क्षमता विकसित करने, मानक विकास, उत्पाद विकास और परीक्षण सुविधाओं, घरेलू और निर्यात बाजार के विस्तार और कौशल विकास आदि का काम किया जाएगा।

हस्तशिल्प, हथकरघा और विकेंद्रीकृत इलेक्ट्रॉनिक करघों के समूह, जिनमें कम से कम पांच हजार करघे हों (हथकरघे और इलेक्ट्रॉनिक करघे) को विश्वस्तरीय बुनियादी और उत्पादन सुविधा प्रदान करने लिए एक समग्र समूह विकास योजना बनाई गई है। इसके अंतर्गत् निम्न मेगा समूहों के विकास के लिए काम किया जा रहा हैः

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) और शिवसागर (असम) के हथकरघा समूह
नरसापुर (आंध्र प्रदेश) और मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) के हस्तशिल्प
भिवंडी (महाराष्ट्र) और इरोड (तमिलनाडु) के इलेक्ट्रॉनिक करघे
एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना में पहले से चल रही दो योजनाओं एपैरल पार्क्स फार एक्सपोर्ट स्कीम और टेक्सटाइल सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम का सम्मिलन करके बनाई गई। इसका लक्ष्य वस्त्र इंडस्ट्री के विकास की संभावना वाले क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है।

पंचवर्षीय योजना में एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना के अंतर्गत 30 टेक्सटाइल पार्कों के स्थापना को हरी झंडी दिखाई गई। सरकार ने एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना को गत पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रखने का फैसला किया है । पंचवर्षीय योजना के दौरान 10 अतिरिक्त पार्क विकसित किए जायेंगे। ये 40 पार्क चालू होने पर 21,502 करोड़ का निवेश आकर्षित करने के अलावा 9.08 लाख श्रमिकों के लिए रोजगार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) रोजगार प्रदान करेंगे। इनके माध्यम से सालाना उत्पादित सामान की कीमत 38115 करोड़ रुपए होगी।

निष्कर्ष –

जैसा कि पहले भी बताया गया कि पिछले कुछ समय से सरकार के नीतिगत उपाय की शुरूआत की वजह से, वस्त्र उद्योग पिछले छः दशक के मुकाबले आज कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। मूल्य के हिसाब से यह उद्योग जहां छः दशक पहले 3 से 4 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा था वहीं आज 8 से 9 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ रहा है। वस्त्र उत्पादन और निवेश में लगातार बढ़ोतरी से इस उद्योग का विकास प्रदर्शित होता है। वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है, देश के व्यापारिक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 13.5 प्रतिशत की है। मल्टी फाइबर व्यवस्था (एमएफए) के समाप्त होने के बाद नई तकनीकों और क्षमता विकास के द्वारा उद्योग ने विकास की नए सोपान तय किए हैं। एमएफए के बंद होने के एक साल के भीतर भारतीय निर्यात में 22 प्रतिशत की दर से विकास हुआ है। मानव संसाधन विकास (एचआरडी) एक इण्डस्ट्रियल संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण निवेश है। समूचे विश्व

कपड़ा बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा है, और इस परिदृश्य में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बाजार हिस्सेदारी सुधारने और आयातित कपड़ों की प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए मानव संसाधन विकास के मुद्दे पर ध्यान देना जरूरी है। मानव संसाधन के विकास के पीछे मूल विचार उपलब्ध इंटेलेक्चुअल कैपिटल का अधिकतम उपयोग कर उत्पादकता और वस्त्र उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना है। परिधान टेक्सटाइल क्षेत्र में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता हो जाएगा। इस बात की स्वीकृति राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद (एनएमसीसी) और योजना आयोग के माध्यम से की गई है। रोजगार के अवसरों में विकास के अवसर को पूरा करने के लिए शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को लगभग छह लाख श्रमिकों को प्रशिक्षित करना होगा। इस प्रकार मै अपने इस शोधपत्र में भारतीय वस्त्र उद्योग का विकास, अर्थव्यवस्था व् रोजगार में इसका योगदान,वस्त्र नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार इसकी में स्थिति का विवेचनात्मक अध्ययन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर चुका हूँ |

सन्दर्भ सूची –

१. इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टेट पालिसी,लिब्रलाइजेशन एंड ग्रोथ,मनोहर पब्लिकेशंस, नई दिल्ली,१९९८ पेज न. १२-१४
२. भारतीय अर्थव्यवस्था,एस.चाँद एंड कंपनी लिमिटेड,नई दिल्ली,२००४,पेज न. ३४
३. लेबर प्रोब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री,एशिया पब्लिशिंग हाउस,मुंबई,१९६५ पेज न. २७
४. इंडिया इंडस्ट्री, पोलिसीज एंड परफॉरमेंस, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस,नई दिल्ली, १९८५, पेज न. ५५
५. श्रम अर्थशास्त्र एवं सामाजिक सुरक्षा,साहित्य भवन पब्लिकेश्न्स,आगरा,२००५ पेज न.४२
६. द कॉटन मिल इंडस्ट्री इन इंडिया,ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस,नई दिल्ली,१९८६,,पेज न.६५
७. डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स,कल्याणी पब्लिशर्स,लुधियाना,१९९० पेज न.२२-२३
८. व्यवसायिक पर्यावरण,साहित्य भवन पब्लिकेशन,आगरा,२००६ पेज न.३१
९. लेटेस्ट स्टैटिस्टिकल मेथड्स,एस.चाँद एंड कंपनी लिमिटेड,नई दिल्ली,२००२ पेज न.१०-१२
१० आर्थिक विकास एवं नियोजन,एस चाँद एंड कंपनी लिमिटेड,नई दिल्ली,२००५,पेज न.५
११. इंडियाज टेक्सटाइल सेक्टर : ए पालिसी एनालिसिस,सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, १९९३ पेज न. ६-८